



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 4 जुलाई, 2006/13 आषाढ़, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जुलाई, 2006

संख्या एल० एल० आर०-डी०(६)१७/२००६-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक १-७-२००६ को प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव।

2006 का अध्यादेश संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2006

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2006 है। संक्षिप्त नाम

1977 का 12. 2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इससे पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 67 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 67 का प्रति-स्थापन।

“67. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.—(1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण होगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) अध्यक्ष; और

(ख) ऐसे अन्य सदस्य, जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, यदि समीचीन समझे, किसी भी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोनों, नियुक्त कर सकेगी।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जो ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और जो ऐसे निषन्धनों और शर्तों के अधीन होंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य किसी भी प्रकार के वेतन के हकदार नहीं होंगे, परन्तु ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसे उक्त प्राधिकरण द्वारा बनाए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।”।

धारा 68
का प्रति-
स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 68 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“68. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का निगमन.—(1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जब तक उत्साहित न हो, एक निगमित विकास होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी तथा धारा 66 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(2) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 67 के अधीन गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से उत्साहित कर सकेगी, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए और उक्त प्राधिकरण तदनुसार उत्साहित हो जाएगा ।

(3) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को, उत्साहित करने की तारीख से ऐसी सभी सम्पत्ति, परिसम्पत्तियाँ, दायित्व, विधियाँ, शोध्य रकमें, जो प्राधिकरण द्वारा वसूली योग्य और कर्मचारी जो उसमें निहित हैं;

यथास्थिति, ऐसे प्राधिकरण या निगम या अभिकरण जैसा राज्य सरकार विनिश्चित करे, द्वारा वसूली योग्य होंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ।” ।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।

प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 3 of 2006.

**THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2006**

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty Seventh year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2006.

Short title.

12 of 1977.

2. For section 67 of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (herein after referred to as the "principal Act") the following shall be substituted, namely:—

Substitution of section 67.

"67. *Special Area Development Authority.*—(1) Every Special Area shall have Special Area Development Authority, which shall consist of:—

(a) the Chairman ; and

(b) such other members as the State Government may determine from time to time,

who shall be appointed by the State Government.

(2) The State Government may, if consider expedient, appoint Vice-Chairman or Chief Executive Officer or both, for any Special Area Development Authority.

(3) The Chief Executive Officer shall be a whole time officer of the Special Area Development Authority who shall receive such salary and allowances and shall be subject to such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(4) The Chairman, Vice-Chairman and Members shall not be entitled to any salary but shall receive such allowances as may be prescribed.

(5) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by regulations made by the said Authority.”

Substitution of section 68.

3. For section 68. of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“68. *Incorporation of Special Area Development Authority.*—
(1) Every Special Area Development Authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, unless abolished, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall sue and be sued by the name specified in the notification under subsection (1) of section 66.

(2) The State Government may by notification in the Official Gazette abolish the Special Area Development Authority constituted under section 67 of the Act from such date as may be specified therein and the said Authority shall stand abolished accordingly.

(3) On and with effect from the date of abolition of the Special Area Development Authority all properties, assets, liabilities, funds, dues and staff which are realisable and vested in the said Authority shall be realisable and shall vest in such authority or corporation or agency, as the case may be, as the State Government may decide.”